**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding the clarification of the government on their stand on Economic and Caste Census 2020 and political reservation of OBCs.

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** Thank you, Sir. There is an urgent need for the Centre to clarify the stand on Economic and Caste Census 2020 and the pollical reservation of OBCs. सरकार ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया था, वह ऑफिशियल जवाब यह है कि ओबीसी आरक्षण का इम्पीरिकल डेटा था, उसमें पूरी तरह से एक्यूरेसी नहीं है और जो जवाब स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया था I would just like to quote it. It says:

> "…that the Parliamentary Committee on Rural Development presented to the Lok Sabha Speaker on 31st August, 2016 on Socio Economic and Caste Census. The Ministry of Home Affairs claimed that this data was 98.87 per cent accurate and Registrar General of the Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs said the Standing Committee that the data has been examined and 98.87 per cent of this data on individual's caste and religion is error free."

This is what they have said. What is the truth? Fifty-six thousand people in Maharashtra and इस देश के 9 लाख से ज्यादा ओबीसीज, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वे इस आरक्षण से वंचित हैं । तो फिर सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो कहा है, वह सच है, या सरकार ने जो स्टैंडिंग कमेटी को कहा है, वह सच है? इस बात को सरकार स्पष्ट करे । धन्यवाद ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री पी आर नटराजन जी - ।उपस्थित नहीं

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर –उपस्थित नहीं

श्री सौगत राय जी ।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** जी सर ।

**माननीय अध्यक्ष** : सौगत राय जी, आपका मौका खत्म ।

… (व्यवधान)